The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

RE : STRIKE BY SOME RAILWAYMEN

MR DEPUTY SPEAKER Now, Shri Chandrajit Yadav

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) . उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट दीजिए। 14 महीने पहले उत्तर रेलवे मे 10 हजार मजदूरो की हड़ताल हुई और श्रम मंत्री ने लिखित आश्वासन दिया था कि हड़ताल वापस ले लो तो विक्टेमाइजेशन नही होगी और उनकी मागो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। फैसला हो गया लेकिन उनकी मांगें पूरी नही की गई है और 4500 रेलवे कर्मचारी विक्टेमाइज्ड हैं और 55 सस्पेंडेड हैं और बाकी का ब्रेक इन सर्विस हो गया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER So, what does the hon. Member want now ?

श्री भोगेन्द्र झा . मेरा आग्रह यह है कि आप रेलवे मंत्री से कहें, श्रम मंत्री से कहें कि लिखित आश्वासन का खुला उल्लंघन क्यो हो रहा है। अभी वहा पर हजारो मजदूर भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप आदेश दें कि श्रम मंत्री और रेलवे मंत्री इस बात पर अपना ध्यान दें और कम से कम जो लिखित आश्वासन है, उसका पालन हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER · Order

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) · वहां पर रिले भूख हड़ताल चल रही है और रेल-कर्मचारी वहा पर आज से इनडेफनीट हंगर स्ट्राइक पर है। (व्यवधान)

14.05 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*CONTD.*

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सन् 1967 के बाद पिछले चार-पाच वर्ष बाद हमारे देश की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन और उथल-पुथल के वर्ष रहे है, विशेषकर पिछला एक वर्ष देश के राष्ट्रीय जीवन मे एतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओ का वर्ष रहा है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री इन्दिरा गाधी के नेतृत्व में जिस साहस, धैर्य, एकता और दूरदर्शिता से अपने जीवन की और राष्ट्रीय समस्याओ का सामना किया है, वह हमारे देश की एक अभूतपूर्व घटना है। पिछले दो वर्ष मे विशेष रूप से जो घटनाए हुई है, उनसे देश की जनता का मनोबल, देश की जनता का आत्मविश्वास, देश की जनता का साहस और उसकी एकता उभरकर बहुत ही आगे आई। सच कहिए तो एक नया भारत जन्म ले रहा है, जिसमे जनता अपने जीवन के अधिकारों के लिए, अपने कर्त्तव्य के लिए और अपने राष्ट्रीय हितो के लिए कृत-सकल्प दिखाई पडती है। यह एक ऐसा समय है कि अगर हम इस उत्साह को, इस एकता को, जनता के इस मनोबल को और उसके आत्म-विश्वास का ठीक से उपयोग करें, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्रीय जीवन की उन विषमताओ को दूर करने के लिए जिनसे हमारा समाज पीड़ित रहा है, तो मुझे इस बात मे तनिक भी संदेह नही है कि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल होगा और हमारे देश की जनता अपने उस सपने को साकार कर सकती है जिसके लिए वर्षों से हम अपने राष्ट्रीय जीवन में संघर्ष करते रहे हैं, गरीबी मिटाने का संघर्ष, देश की जनता की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करने का संघर्ष, देश और समाज से शोषण को समाप्त करने का संघर्ष, देश को मजबूत और गौरवशाली बनाने का संघर्ष। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमारे देश की जनता ने जिस राजनीतिक बुद्धि और बुद्धि की परिपक्वता का परिचय दिया है और जिस बुध्दिमत्ता और समझ-

दारी का परिचय दिया है और हमारे देश की जनता ने इस संकट के समय में जो काम किया है, वह हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय साथी है। आज हम इसके लिए कृत-संकल्प हैं कि हम अपने देश की जनता के इस उत्साह को, इस एकता को, उसके मनोबल को, उसके संकल्प को देश के पुनर्निर्माण में उपयोग करें।

मुझे अफ़सोस होता है कि हमारे देश के कुछ विरोधी दल और हाल के चुनावों में धराशायी होने के बाद, हारने के बाद, देश के इस उत्साहजनक वातावरण को, देश की एकता को तोड़ मरोड़ कर तस्वीर जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीमन्, राजनीति जीवन में, प्रजातान्त्रिक पद्धतियों में विचारों में मतभेद हो सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी नीति और कार्यक्रम पर काम करने का पूरा अधिकार है लेकिन राष्ट्रीय हितों का ध्यान सब को रखना चाहिए। प्रजातन्त्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता का मनोबल टूटने न पाय, राष्ट्रीय निर्माण में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता ने जिस सम्पत्ति को अपने राष्ट्रीय एकता से अर्जित किया है जिस उत्साह को अर्जित किया है, हम उस को धुंधला न होने दें। आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि भारतीय जनता, भारतीय नेतृत्व और भारतीय सरकार गौरव और गरिमा, उस की प्रतिष्ठा आज दुनिया में बढ़ी है। आज इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि भारतीय सरकार ने, भारत की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में जिन आदर्शों और सिद्धान्तों के लिए बड़े संतोष के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़े धैर्य के साथ जब बड़ी बड़ी शक्तियां उसे कसने की कोशिश कर रही थी, जिस दूरदर्शिता के साथ, जिस बुद्धिमत्ता के साथ इन समस्याओं का निराकरण किया है, उस से हमारे देश का गौरव और सम्मान बढ़ा है। यह देश के हित में होगा और यह राष्ट्र के हित में होगा कि हम इस वातावरण को पुष्ट करें। जीवन में विचारों में मतभेद होते रहेंगे। राजनीतिक संघर्ष भी चलते रहते हैं और हम चाहते हैं कि वे चलते रहें। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में प्रजातन्त्र अक्षुण्ण बना रहे। आज यह कहा जाता है कि इन चुनावों से प्रजातन्त्र कमजोर हो गया है, एक पार्टी और उस के नेता की तानाशाही इस मुल्क में कायम हो गई है। यह कहा जा रहा है कि विरोधी दलों को समाप्त किया जा रहा है और एक कुचक्र रचा जा रहा है। श्रीमान्, यह बात वास्तविकता के बिल्कुल प्रतिकूल है यह मैं समझ सकता हूं कि विरोधी दलों के हारने के बाद एक अजीब सी मन स्थिति में वे आ गये हैं और उन का मनोबल टूटा हुआ है लेकिन यह उन के हित में नहीं है कि वे वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश करें। विडम्बना आज हम यह देखते हैं कि एक तरफ साम्प्रदायिक विचारधारा का नेतृत्व करने वाली पार्टी जनसंघ है और दूसरी तरफ उग्रवादी वामपंथी दल अपने को कहने वाला सी० पी० एम० है और दोनों ही इन प्रश्नों पर एक तरह से खेल रहे हैं, एक से विचार व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अजीब सी विडम्बना है। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि प्रजातंत्र समाप्त हो रहा है। मैं इन से प्रार्थना करता हूं कि ये इतिहास पर सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ दृष्टि डालें। भारतीय जनता का अपना इतिहास है, हमारी अपनी परम्परायें हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश की जनता ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया। हमने कुछ एक मुट्ठी भर लोगों पर विश्वास नहीं किया। हम उन पर निर्भर नहीं रहे। हमने किसी शक्ति और हथियारों पर विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया की सब से मजबूत साम्राज्यवादी सत्ता को अगर उखाड़ कर फेंकना है तो भारत की करोड़ों जनता जब तक आजादी के संघर्ष में नहीं उतरेगी, उसकी हिस्सेदार और भागीदार नहीं

[श्री चन्द्रजीत यादव]

बनेगी, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने उस संघर्ष को भी कुछ सिद्धान्तों और आदर्शों पर चलाया। उन सिद्धान्तों पर चल कर ही हमने आजादी हासिल की। भारत की करोड़ों जनता उस आजादी के संघर्ष के अन्दर हिस्सेदार और भागीदार बनी। आज भी देश की करोड़ों जनता देश के पुनर्निर्माण के काम में, राष्ट्रीय निर्माण के कामों में लगी हुई है। हम चाहते भी यही हैं कि देश के किसान, मजदूर मेहनत करने वाले, नौजवान, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग के लोग राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कामों में भागीदार और हिस्सेदार बनें। हमें इस बात पर गर्व है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने आजादी के लिए संघर्ष किया और आजादी हासिल करने के काम में देश की जनता भागीदार बनी और आज भी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश की जनता पुनर्निर्माण और समाज की रचना में भागीदार और हिस्सेदार बनाई गई है। आज देश की करोड़ों जनता के सामने समस्याओं को हमने खोल कर रख दिया है,। जब हमें इन शक्तियों की तरफ से चुनौती दी हमारे आदर्शों के लिए, सिद्धान्तों के लिए, गई, जीवन और समाजके मूल्यों के लिए, चुनौती दी गई तो हमने यह उचित नहीं समझा कि हम उससे आंख बंद करके अपने रास्ते को बदल दें। हमने उन समस्याओं को जनता के सामने रखा। सभापति महोदय, इस सदन का सभापतित्व आज आप कर रहे हैं और आपको मालूम ही है कि पिछली बार सदन के अन्दर कुछ काम नहीं हो पाए थे। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझा कि अगर देश के सामने कुछ चुनौतियां हैं, तो जनता को इस बात का निर्णय करने का मौका दिया जाना चाहिये कि कौन सा रास्ता देश की जनता के हित में है। यही एक बेहतरीन रास्ता हो सकता था जो उन्होंने अख्त्यार किया। सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद दूसरे निर्णय हुए। श्रीमती गांधी ने प्रजातांत्रिक नेता होने के नाते उन निर्णयों का आदर किया। उनके समाधान में चाहे उससे हमें देर हुई और चाहे हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा हुई लेकिन उन्होंने कहा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय देता है तो हमें उसका आदर करना पड़ेगा। लेकिन उस न्यायालय से भी बड़ा देश में एक और न्यायालय है, प्रजातंत्रीय पद्धति में उससे भी एक बड़ा न्यायालय होता है, जिस को जनता का न्यायालय कहा जाता है। श्रीमती गांधी ने कहा कि अगर देश की जनता के हितों के लिए रास्ते का चयन करना है और देश की जनता के लिए काम करने में हमारे सामने बाधायें पैदा हो रही हैं तो देश की जनता के न्यायालय के समने हमें जाना पड़ेगा। वह देश की जनता के सामने गई। क्या यह प्रजातंत्र की हत्या है? क्या यह सही है कि ऐसा करके उन्होंने तानशाही का रास्ता अख्त्यार किया? क्या यह सच नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो बेहतरीन और सब से अच्छा प्रजातांत्रिक-रास्ता और तरीका हो सकता था, उसको उन्होंने अख्त्यार किया? देश की प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, साम्प्रदायिक शक्तियों ने कोई कोर कसर उठा न रखी और महागठबन्धन का निर्माण किया उस रास्ते पर हमको चलने से रोकने के लिए। लेकिन हमने अपने विचारों को, अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को जनता के सामने रख दिया। उस पर जनता ने अपना निर्णय दे दिया। मुझे खुशी होती अगर इस सदन के सामने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को देश में मजबूत करने के लिए कहा जाता कि प्रजातांत्रिक रास्ते को अपनाया गया और जो जनता ने निर्णय किया है, उसे हम स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन आज उलटा कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि प्रजातंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी तानाशाह हो रही हैं। ये सब बातें सच्चाई से बिल्कुल विपरीत हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है। वास्त-

विकता से दूर हैं। सच्चाई यह है कि केवल हिन्दुस्तान की जनता ही नहीं दुनिया भी इस सच्चाई को मानती है कि दुनिया का सब से बड़ा प्रजातांत्रिक देश जो है हिन्दुस्तान उस में प्रजातंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह नैतिकता का तकाज़ा था कि इस सच्चाई को स्वीकार करके हम चलते।

आज कहा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा एक गलत नारा है, इसके अन्दर गम्भीरता नहीं है। लेकिन यह नारा केवल एक नारा मात्र नहीं है। यह हमारी सरकार का और हमारी जनता का संकल्प है एक अभियान है जो हमने चलाया है। हमने संकल्प किया है कि इस देश में गरीबी हटाने के लिए हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। मुझे खेद है कि आज चीजों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिशें की जाती हैं। जो इस तरह की बातें कहते हैं उनको खुद भी मालूम है और वे स्वयं भी जानते हैं कि जो बातें वे कह रहे हैं, उन में सच्चाई नहीं। लेकिन हारे हुए, पराजित हुए लोग अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आज इस प्रकार की बातें कह रहे है और वे खुद भी इस बात को जानते है कि जो बात वे कह रहे है, उस में सच्चाई नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कुछ बहुत गम्भीर अरोप लगाए है। वह एक पार्टी के नेता है। अगर वह इस तरह के गम्भीर आरोप न लगाते तो सच जानिये कि मैं बोलता नहीं। लेकिन उनके इन गम्भीर आरोपो का उत्तर देने के लिए मुझे बोलना पड रहा है। तीन चार बुनियादी आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि श्रीमती गांधी तानशाह हो रही है और हर गलत या सही रास्ता इस्तेमाल करने के लिए वह तैयार हैं, नैतिक मान्यताओं के प्रति उनके दिल में कोई कद्र नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगला देश में जो नीति अपनाई गई वह गलत नीति है। आज भी उनका विश्वास है कि हमें पहले कदम उठाना चाहिये था। यह भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बरबाद क्यों नहीं किया गया, आज भी पाकिस्तान को इस काबिल क्यों छोड़ दिया गया कि वह हमारे लिए संकट बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के दबाव के कारण या रूस की सहायता के कारण हमने बंगला देश मे विजय प्राप्त की। ये ऐसे अरोप है जो बेबुनियाद तो हैं ही, निराधार तो है ही, भ्रामक भी हैं और देश की जनता को गलत रास्ते पर ले जा भी सकते हैं। जहा तक पहली बात का सम्बन्ध है मैंने बता दिया है कि जो भी काम हम इस देश मे करना चाहते है, हम चाहते यही है कि संसदीय व्यवस्था इस देश में उत्तरोत्तर मजबूत होती जाए, हम चहाते है कि जनता को इन कामों के अन्दर निरंतर भागीदार बनाया जाए, हम चाहते हैं कि देश के अन्दर शासन का विकेन्द्रीयकरण हो। इस आशा और निष्ठा के साथ ही हम अपने कामों को कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कारण यह है कि मैं एक राजनीति का विद्यार्थी हूं और इस नाते मैं यह भी जानता हू कि देश के प्रतिक्रियावादी विचारधारा के जो नेता है वे समय को नहीं पहचान पाते, गति को नहीं पहचान पाते, समाज में बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को नहीं पहचान पाते, समाज में उत्पन्न होने वाले नए मूल्यों और विचारों को नहीं पहचान पाते और ऐसे जो रूढिवादी और समाजविरोधी नेता होते हैं वे भविष्य के नेता नहीं बल्कि भूत के नेता होते हैं। बाजपेयी जी भी भूत के नेता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि श्रीमती गांधी तानाशाह हो रही हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि श्रीमतीगांधी ने ऐतिहासिक

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने स्थान को, अपने पद को खतरे में डाल कर कदम उठाये हैं। उनके सामने केवल एक बात रही है। जो आदर्श हैं, जो सिद्धान्त है और जिन की वजह से भारत का सम्मान दुनिया के अन्दर होता है और जिन को राष्ट्रीय लड़ाई के ज़माने में भी हमने अपने सामने रखा और आगे भी देश की रचना के लिए, देश के पुनर्निर्माण के लिए, नए समाज की रचना के लिए, हम बनाए रखना चाहते है, उनकी रक्षा कैसे की जाए। उन आदर्शों को वह छोड़ना नही चहती, उन पर वह दृढ़ रही है। कितने तूफान आए, कितनी ही ताकतें उन से टकराने के लिए आगे बढ़ी लेकिन वह जानती थी कि जिन आदर्शों और सिद्धान्तो की वह रहनुमाई कर रही हैं, वे देश की करोड़ो गरीब जनता के आदर्श और सिद्धान्त हैं, देश की करोड़ों जनता मे उन आदर्शों और सिद्धान्तों के लिए आस्था है, निष्ठा है और जनता कभी भी चाहे जितनी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, उनको छोड़ने वाली नही हैं। श्रीमती गांधी ने उन सिद्धान्तों और आदर्शों को नही छोड़ा। चाहे राष्ट्रीय जीवन के अन्दर उनको राजनीतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ा, चाहे अपनी संस्था या अपने दल अन्दर, मुकाबला करना पड़ा, देश के महागठबन्धन का मुकाबला करना पड़ा, पाकिस्तानी हमले के समय चाहे उसका मुकाबला करना पड़ा, दुनिया के सब से बड़े साम्राज्यवादी देश, अमरीका की धमकियों का मुकाबला करना पड़ा लेकिन श्रीमती गांधी का विश्वास उन आदर्शों और सिद्धान्तों में अक्षुण्ण रहा। वह साहस के साथ, हिम्मत के साथ देश की जनता का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ी और आज भी बढ़ रही हैं।

यह भी कहा गया है कि बंगला देश में कदम बहुत देर से उठाया गया। मुझे अफसोस है कि कुछ ऐसे लोग भी देश में हैं जो इतिहास से सबक सीखने को तैयार नहीं, ऐसा करने से इन्कार करते हैं, जो सच्चाई को देखते नहीं, उसको देखने के लिए आंख नहीं खोलना चाहते आंख बन्द करके खाना चाहते हैं। जो नतीजे सामने हैं उनको देख कर भी अगर श्री वाजपेयी इस तरह की बातें कहते हैं और तब कहते हैं जबकि सारी दुनिया इस बात की प्रशंसा करती है, एक करोड़ शरणार्थी जो भारत में आए उनके आने के बाद भी और तरह तरह के उकसावे और प्रोवोकेशंस जो दिए गए, उनके बावजूद भी और देश के अन्दर सारी पार्टियां श्रीमती गांधी की सरकार के ऊपर टूटी पड़ी थी और मांग कर रही थी कि आप जल्दी कदम उठाये, तो आश्चर्य हुए बगैर नही रहना है। लेकिन वह जानती थी कि उन का कदम तभी उठेगा, जबकि वह देश के राष्ट्रीय हित, हमारी जनता के हित और बंगला देश की जनता के हित मे होगा। उन्होंने सामयिक कदम उठाया, जिस की उपलब्धि बंगला देश के जन्म के रूप मे हुई। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कभी इस प्रकार सिद्धान्तो और आदर्शों की बुनियाद पर एक देश का जन्म किसी एक सरकार की मदद से नही हुआ है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक कदम उठा कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। अगर आज श्री वाजपेयी इस कदम को असामयिक समझते हैं, तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि वह एक मरती हुई विचार-धारा के, जो इतिहास पीछे पड़ गया है, जिस विचार-धारा का कोई भविष्य नहीं है, उसका प्रतिनिधि होने के नाते ऐसी बात कहते हैं।

वह कहते है कि सरकार ने युद्ध-विराम क्यों किया। हम कब चाहते थे कि हम पाकिस्तान पर हमला करें? हम ने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है। पाकिस्तान को तोड़ने का हमारा कभी इरादा नही था—आज भी नही है और भविष्य में भी नहीं होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ शांति और दोस्ती के साथ रहे और अपनी जनता की समस्याओं को

हल करे, बजाये इस के कि वह बराबर हिन्दुस्तान की तरफ उंगली उठा कर अपनी समस्याओं के बचने के लिए शुतरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन गड़ाये रखे ।

लेकिन जब बंगला देश की जनता की इच्छा नहीं मानी गई, जब बंगला देश के बहादुर सेनानियों को शक्ति के बल पर दबाने का प्रयास किया गया, एक ऐतिहासिक आन्दोलन को पराभूत करने की चेष्टा की गई, जब बंगला देश की बहादुर जनता उस के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और तीस लाख आदमियों का नर-संहार करने के बाद भी पाकिस्तान के फौजी तानाशाहों की खून की प्यास नहीं बुझी और उन्होंने भारत की धरती की तरफ आंख उठाई, तो समय पर उस का वह जवाब दिया गया, जिस को पाकिस्तान के नेता न आज भूल सकते हैं और न भविष्य में भूल सकेंगे । जैसा कि मैं ने कहा है, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक सामयिक कदम उठाया । जब बंगला देश का जन्म हो गया, बंगला देश की बहादुर जनता को आजादी मिल गई, प्रजातंत्र का हक मिल गया, तो भारत को यह कहने में एक क्षण भी नहीं लगा कि हमारी फौजें वापिस आयेंगी, हम पाकिस्तान को नहीं जीतना चाहते हैं । अगर यह बात श्री वाजपेयी की समझ में नहीं आती है, तो मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री वाजपेयी समझते थे कि भारत सरकार पाकिस्तान को जीतने के लिए हमला कर रही है, क्योंकि उन की पार्टी का यह नारा रहा है कि पाकिस्तान को समाप्त करो । हमारे और उन के विचारों में यह मौलिक मतभेद है । इस लिए वह इस बात को नहीं समझ सकते ।

हम पाकिस्तान को कमजोर या समाप्त नहीं करना चाहते हैं । लेकिन पाकिस्तान की जनता का यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के जन्म से ही उस को प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक नेतृत्व मिला है । जब उस नेतृत्व में परिवर्तन भी हुआ, तो उस को फौजी तानाशाहों का नेतृत्व मिला । पाकिस्तान की जनता को कभी एक लोकप्रिय नेतृत्व नहीं मिला, यही उसका दुर्भाग्य रहा है । बंगला देश की जनता को अपनी इच्छाओं और भावनाओं, आशाओं, अरमानों और आकांक्षाओं के अनुरूप एक लोकप्रिय और प्रजातांत्रिक नेतृत्व मिला और आज बंगला देश और भारत समान विचारों और आदर्शों के आधार पर एक मैत्री की संधि से जुड़े हुए हैं । हमारी शुभकामना है कि पाकिस्तान को भी उसी प्रकार का लोकप्रिय शासन मिले और भारत तथा पाकिस्तान दोस्ती, सहयोग और मैत्री के साथ रह सकें । यह हमारा दृष्टिकोण है और हम जनसंघ के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं ।

श्री वाजपेयी ने यह भी कहा कि रूस की मदद के बगैर बंगला देश नहीं बन सकता था । इस सदन में—और बाहर भी—हम ने, हमारी पार्टी और नेता ने और देश की जनता ने रूस के प्रति आभार प्रकट किया है । रूस ने जिस मैत्री का प्रतिपादन किया, जिस मैत्री की भावना के साथ वह हमारे साथ खड़ा हुआ, उस के लिए हम हमेशा उस का आभार मानेंगे । हमारी और रूस की मैत्री विचारों और आदर्शों पर आधारित है और हम चाहते हैं कि वह आगे बढ़े । लेकिन यह कहना देश का और देश की जनता का अपमान होगा कि बंगला देश रूस की मदद के बगैर नहीं बन सकता था । जो जनसंघ के नेता बराबर राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीयता के एकमात्र इजारेदार समझते हैं, अगर उन की समझदारी यही है कि बंगला देश केवल रूस की मदद से बन सका, तो मुझे उन की समझदारी पर तरस आता है । मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश की जनता ने, हमारे बहादुर सैनिकों ने, हमारी फौज के अफसरों ने और हमारे

[श्री इन्द्रजीत यादव]

नेतृत्व ने जिस सूझ-बूझ और समझदारी के साथ बंगला देश की जनता का साथ दिया, उस का/गौरव और श्रेय हमारे देश की जनता, हमारी फौज और हमारे नेतृत्व को है। यह कहना सच्चाई से इन्कार करना है कि किसी अन्य देश को उस का श्रेय जाता है।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि हम ने रूस के दबाव में आ कर युद्ध विराम किया और रूस के दबाव में हम कोई और गलती करने वाले हैं। एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में और उस के बाहर हम कह चुके है कि हमारी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नीति की एक ही कसौटी है कि जो काम हमारे देश और हमारी जनता के हित में है, हम उसी को करना चाहते हैं। हम किसी देश के दबाव को एक क्षण के लिए भी स्वीकार करने के लिए तैयार नही हैं। आज अगर दुनिया मे कही हमारा सम्मान होता है, तो इस लिए होता है कि विभिन्न विषयों पर हमारे अपने विचार, अपने आदर्श और अपने निर्णय होते है और मुझे खुशी है कि दुनिया मे ऐसी शक्तियां भी है, जो हमारे निर्णय का आदर और सम्मान करती हैं। रूस के नेताओं ने बराबर कहा है कि हम भारत के साथ बराबरी की मैत्री चाहते हैं, हम भारत पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं। भारत के नेताओं ने भी यही कहा है। इस के बावजूद बार-बार इस बात को दोहराया जाता है कि हम रूस के दबाव में कोई काम करना चाहते हैं।

जनसंघ के नेताओं को इस बात की आदत पड़ गई है। जब से हम ने आजादी हासिल की है, वे कहते रहे है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ है, जिस से उस को शक्ति और हथियार मिल रहे हैं और वह अमरीका की मदद से आगे बढ़ रहा है। जनसंघ की ओर से बराबर हमारी वैदेशिक नीति पर हमला किया जाता रहा है। वह कहता रहा है कि पाकिस्तान की वैदेशिक नीति हम से अच्छी है, पाकिस्तान अमरीका से भी दोस्ती करता है, चीन से भी दोस्ती करता है और रूस को भी प्रसन्न रखना चाहता है, हम दुनिया में अकेले हैं, हमारा कोई मित्र नहीं है, आदि।

आज सबसे बड़े राष्ट्रीय संकट की घड़ी में यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान की वैदेशिक नीति की तुलना में, जिस का गुणगान जनसंघ के नेता करते रहे हैं, हमारी वैदेशिक नीति सही थी। आज भी उन की समझ में यह बात नही आ रही है कि हमारी वैदेशिक नीति एक स्वतंत्र वैदेशिक नीति है, विश्व शान्ति और विश्व सहयोग की वैदेशिक नीति है, दुनिया के दूसरे देशों से भाई चारे और मैत्री की वैदेशिक नीति है, अपने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों हितो को जोड़ कर आगे बढ़ने की वैदेशिक नीति है। हमारी वैदेशिक नीति एक क्षण के लिए भी इस बात की इजाजत नही देती है कि हम दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति के दबाव को मानें और अपनी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को अपनी आजादी को किसी के पास गिरवी रख दें। हमे चाहे कितने भी संकटों का सामना करना पड़ा, हम इसी नीति पर चलते रहे हैं। आज जो इस प्रकार के आरोप लगा कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वह स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराओं के लिए उचित नही है।

जैसा कि मैं ने शुरू में कहा है, देश ने एक नया आत्म-विश्वास, दृढ़ एकता और संकल्प हासिल किया है। यह देश जितना महान् है, इस देश की जनता जितनी महान् है, उतनी ही महान् देश की समस्यायें हैं। आज कौन इस बात से इन्कार कर सकता है कि हमारे लाखों होनहार नौजवान बेकारी के शिकार हैं, हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। हम ने देश में बढ़ती हुई महंगाई और अमीरी तथा गरीबी की बढ़ती हुई खाई को दूर करने का संकल्प किया है। लेकिन इन

समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपने कदम तेजी से बढ़ाने होंगे, हमें अपने तौर-तरीके बदलने पड़ेंगे। अब पुराने तरीके इस देश में नहीं चल सकते। हम जानते हैं कि हम करोड़ों रुपये अपने देश की जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवंटित करते हैं, लेकिन वह रुपया खर्च नहीं होता है। हमें नौकरशाही का मौजूदा स्वरूप, कार्यालयों के पुराने तौर-तरीके लाल फीताशाही और काम करने की मन्द गति को बदलना पड़ेगा। आज देश की जनता यह चाहती है कि हम उस के जीवन के उत्थान के लिए, उस की प्रगति के लिए, तेजी से कदम बढ़ायें।

मैं जानता हूं कि इस सवाल को बहुत हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन हम ने कोई रास्ता निकालना है। अगर देश की जनता, देश का नेतृत्व और देश की सरकार बंगला देश जैसे अभूतपूर्व राष्ट्रीय संकट का दृढ़ता, संकल्प और इरादे के साथ हल निकाल सकते हैं, तो फिर देश की बेकारी और गरीबी का भी हल निकाला जा सकता है। मैं चाहता हूं कि उसी दृढ़ता के साथ, उसी संकल्प के साथ, उसी इरादे के साथ आज हम आगे बढ़ें, हमारे कदम आगे बढ़ें ताकि हम एक नया हिन्दुस्तान, एक मजबूत हिन्दुस्तान, गरीबी अमीरी के भेदभाव को समाप्त करने वाला हिन्दुस्तान अपने देश के अंदर बना सकें।

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि हम ने आत्म-निर्भरता का नारा दिया है। बहुत सही और उपयुक्त नारा है। इस नारे का कोई मजाक बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी तस्वीर दुनिया में एक भिखारी की तस्वीर थी। जब हम पी० एल० 480 के गेहूं के लिए हाथ फैलाते थे तो हमारे देश के आत्म-सम्मान को धक्का लगता था। लेकिन हम जानते थे कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था। इस देश के करोड़ों गरीबों के पेट भरने के लिए हम को कुछ करना था। हमारी योजनाएं चल रही थी. किसानों को पानी देने की, बिजली देने की, खेती में नई क्रान्ति लाने की योजनाएं चल रही थी, और उसी का नतीजा यह है कि आज इस चुनाव मे जाने से पहले भारत सम्मान और गौरव के साथ अपना सिर ऊंचा कर के कह सकता था कि आज से एक मुट्ठी भर चावल के लिए भी हम को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारा देश कृषि के अंदर आत्म-निर्भर है। लेकिन उद्योग के अंदर बहुत कुछ करना है। उद्योग के अन्दर इजारेदारी अपनी जड़ जमाए बैठी है। उद्योग के अंदर हम ने इस बात का संकल्प किया है कि मोनोपली को इस देश से खत्म करना है। लेकिन मोनोपली की हमारे आर्थिक ढांचे पर, हमारे प्रशासन पर और हमारे समाज पर आज भी जो छाप है उस को अगर हम अभी दूर नहीं करेंगे और इस के लिए प्रभावकारी कदम नहीं उठाएंगे तो मुझे इस बात का भय है कि जो संकल्प हमने किया है जो कार्यक्रम बनाया है वह तेजी के साथ पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध मे सरकार प्रभावकारी कदम उठाए।

अंत में मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनसंघ के मित्र और हमारे सी. पी. आई. (एम) के दोस्त ये दोनों सच्चाई को देखने की कोशिश करें। यह कहना कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, यह कहना कि प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, यह कहना कि विरोधी पार्टियों को समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है, यह वास्तविकता पर परदा डालना तो है ही, खुद अपने को नहीं देखना है। इस देश की जनता ने हिंसा की राजनीति को हमेशा से इनकार किया है। इस देश की जनता ने साम्प्रदायिकता की कोशिश करने वालों को चाहे वह भाषा के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम

[श्री चन्द्रजीत यादव]
पर, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर जो साम्प्रदायिकता करने की कोशिश करते हैं उन को भी समाप्त करने की कोशिश की है।... ...(व्यवधान)...

श्री हुकम चन्द कछवाय : साम्प्रदायिकता है क्या, उस की परिभाषा आप ने कभी की ?

श्री चन्द्रजीत यादव श्रीमन्, आज हमें इस बात का गर्व होता है कि अगर सुदूर पूर्व में कहीं नागालैंड और मिजोराम में, मेघालय में, नेफा में, अरुणाचल में, हमारे उस क्षेत्र में रहने वाले कभी यह महसूस करते थे कि देश का शासन उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, उनको गुस्सा था, क्रोध था, असंतोष था तो हमने बड़े धैर्य के साथ उनके दिल की बात समझने की कोशिश की, हमने उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की और आज क्या हमें इस बात का गर्व नहीं हो सकता कि देश में एक ऐसा राष्ट्रीय वातावरण बन रहा है, देश में एक ऐसी राष्ट्रीय धारा बह रही है जिसके अन्दर हमारे मिजोराम, मेघालय, अरुणाचल और सुदूर पूर्व के लोग, काश्मीर और केरल के लोग और हमारे पश्चिम में सौराष्ट्र और गुजरात के लोग सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक हमारा देश है, एक हमारा राष्ट्र है, हम इस राष्ट्र के अंग हैं। आज हम प्रजातान्त्रिक पद्धति से उनकी समस्याओं को समझने और हमदर्दी से उनको हल करने का कार्य कर रहे हैं। हमने भूल में गलती की। उसको दूर करके आगे के लिए एक ऐसा हिन्दुस्तान बनाने का काम करें जिसमें हिन्दुस्तान के कोने-कोने में रहने वाला नागरिक चाहे वह किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, यह महसूस कर सके कि यह देश उसका है। इस देश की कुछ राष्ट्रीय धारायें हैं, कुछ राष्ट्रीय मूल्य हैं, आज उसकी रक्षा के लिए हम आगे बढ़ें। इसलिए ऐसे समय में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास न किया जाय जिससे जनता के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाय।

मैं भारतीय जनसंघ के नेता से केवल एक ही बात कह सकता हूं। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीय दर्शन की वह बहुत दुहाई देते हैं और उसका एकाधिकारी अपने को मानते हैं। भारतीय दर्शन एक चीज और सिखाता है कि ऐसे जमाने में जरा आत्म-परीक्षा भी करनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि वह जरा आत्म-परीक्षण भी करें और देखें कि जो गलती की है उसको दूर करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह समय दिया। मैं यह आशा करता हूं कि आज भारत की जनता, भारत की सरकार भारत का नेतृत्व, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस नीति और कार्यक्रम को इस देश में लागू करने के लिए कृत संकल्प है उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना है। मुझे आशा है कि यह देश बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, अपनी समस्याओं का हल निकालने में यह देश कामयाब हो सकेगा और चूंकि इन समस्याओं की ओर हमारे राष्ट्रपति ने ध्यान आकर्षित किया है इसलिए मैं पुनः एक बार इस सदन की तरफ से उनका अभिवादन करता हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore) Mr Deputy-Speaker, Sir, I heard with rapt attention the speech delivered just now by one of the topmost leaders of the Congress Party and I will deal with some facts which he has stated during the latter part of his speech. But prior to that I want to state categorically that the President in his Adress and the speakers of the ruling party here tried in vain to depict a rosy picture of the economic condition of our country.

The facts, if reviewed objectively, bring out the other picture. Subsequent to the

President's Address, the Budget was presented. There also it is claimed that the country is movin g towards the goal of economic progress and social justice. But the facts belie all these tall claims. On the one hand, the ruling party talks of *garibi hatao* and, on the other, they are giving unfettered scope to monopoly, both indigenous and foreign, to exploit the toiling millions of our people throughout the country.

According to the latest figures available, the big industrial houses have been given more licences in the last year than in the previous years. In 1969 the big houses got 33 licences but in 1971 they got 113 licences. What does it indicate ? Is it progress in the fight against monopoly or is it giving full scope to monopoly to spread its tentacles and exploitation more vigorously ?

Here many things are said abuot the Birlas. The Birals are one of the biggest monopoly houses. In this House our party and several parties have raised the demand for the nationalisation of the big mononpoly houses, including the Birlas. But what is taking place here ? The Minister says that the Hindustan Motors is a junk factory and there is nothing to take over. But subsequently twice within six months the price of the Hindustan motor car was increased to the extent of Rs. 600 net. It might be by the order of the Supereme Court. Many things have been done here to undo the order of the Court. I know, in the case of the promotion system prevailing in regard to the Central Government employees, judgment has been given by the Supreme Court long back, but it has not yet been implemented. But as soon as the Supreme Court gave the verdict for the increase in the prices of Hindustan motor car and other passenger cars, the prices have been increased.

Not only that, the Ratnakar Shipping Company got Rs. 6 crores as aid from the Shipping Development Fund Committee.The story goes that the Chairman of this Committee resisted for the last one year the payment of any loan, aid or subsidy to the Ratnakar Shipping Company which is owned by the Birlas. But just prior to the elections, taking advantage of the absence of that particular Chairman, Rs. 6 crores were given to the Birlas. This is the way of fighting the monopoly. And you are giving sermons to us to see what wounderful measures the Indira Gandhi Government is taking to fight the monopoly and remove the poverty of the pepole. But these are your *Garibi-Hatao* actions.

Further I want to state here that it is a peculear method of fighting the monopoly. There are certain companies in West Bengal which have several times asked for expansion licences or for the diversification of their products. They are not given licences on the plea that they are at monopolly concern and that they will not get any licence for expansion. But the same Companies, if they ask for any licence to start a factory to produce the same product in any other province, they are given licences. The Birlas were given a licence for starting a cycle-manufacturing factory in Uttar Pradesh; the Dunlop tyre Co. was given a licencs to start a factory in Madras. But they were not given any licence for expansion in West Bengal. Because, it is West Bengal. This is a peculiar method of fighting the monopoly.

So, I would request the hon. Members to think over it as to whether it is a stunt or, actually, it is a fact that you are fighting against the monopoly.

Not only in the industrial field. Many things have been said here and outside. Just now, Shri Chandrajit Yadav told us many things What about the land reforms ? I do not want to speak of any new ceilng I ask: What are you doing with the existing laws ? It has become an annual affair to say that share-croppers will be evicted. There is a socialistic Government here, the Garibi-Hatao Government, at the Centre. They say that they will distribute land to the landless. But thts is the reality. The share-croppers have no security of land. In one year, they will spend everything for the development of a particular land and the next year, they will be evicted by *jotedars or zamindars*. This is the situation obtaining in the agricultural field.

So many things have been said here about nationalisation of banks and that a new system is being proposed by the Fiance Minister. But I want to know what has actually been done, say, in the last one

[Shri Dinen Bhattacharyya]

year, for giving loans at the time of necessity to ordinary peasantry, the poor peasantry the middle-class peasantry who till their land. What is the system of giving loan to these people? I want to know whether any loan or any aid or any help has been given by the nationalised banks to the poor peasantry. Nothing of the sort.

So far as my experience goes, and I have gone through the countryside, the ordinary people do not get any help. Yes, some people get help. That is the tragedy. Just as in olden days, the Britishers tried to build up a new vested interest, during the Congress rule a systematic effort is being made to build up a new vested interest in the rural sector. These particular sections of people get loan or help from the nationalised banks. But the ordinary people get nothing.

Not only that. What about the small and medium scale industrialists ? Are they getting any help from these nationalised banks ? They are not given any help. Even, the other day, the hon. Minister was claiming that the rate of growth of small-scale industries has been to the extent of 10 to 11 per cent.

But in the mid-term appraisal it is stated that only 3 to 3½ per cent the small scale industries have developed.

Today and also the other day, in the courses of a reply to a call-attention, the Minister said that, in U.P. 40 lakhs of weavers are almost facing starvation. The prices of the yarn have increased; their market is shrinking, their products are not sold; they are getting no market. Ultimately they are now conducting a struggle against all these systems. Not only in U.P. but in West Bengal also so many weavers are there; there is no system of getting of any yarn at a reasonable price, and there is no market for these weavers. This is their condition ! The small scale industries and cottage industries have no place in this 'Garibi Hatao' Raj. Every thing is, as it was for the big and the monopolists. Today what was the reply of the Minister to the call-attention regarding coir workers and coir industry in Kerala ? There also, lakhs of people are suffering because there is no real help, positive help, given to them by the Government. On the other hand, the coir industry workers earn for the country foreign exchange to the extent of Rs. 14 crores every year. Their condition is now really pitiable, and the Minister had to admit it. But whatever he might admit or they might assure, we know that the policy of this Government, materially, is to see that the profits of the big monopolies are not touched; on the other hand, scope is given so that they may make more profits. Then where is the scope for the ordinary poor people and the middle and small sections of industrialists and agriculturists ? There is no scope for them. There is no help for them from the Government which has taken a vow, of course in a camouflaged way, and has given tall assurances that they will remove poverty, they will see that unemployment is romoved, at the earliest But as days go, by the unemployment and the poverty of the people are increasing.

Here in his Address the President has stated that, in spite of all difficulties, the prices have been kept under control. I will cite only one example. Sugar is nowadays used by the ordinary people also. Even one year back it was selling at Rs. 1.75 per kilo ; this was the maximum price. But now everywhere, in Calcutta, in Delhi and also in villages, you cannot get sugar unless you pay Rs. 4 per kilo, This is the case not only with regard to sugar but with other things also. In the case of every item that is used by the common man, the price has gone up, and every day it is going up. After every Budget you will find the price of cigarettes going up ; it happened this time also. The prices of the other commodities are also going up. The common man has no help in this matter ; Government says something but, in practice, something else happens.

So, this is the situation everywhere throughout India. In this situation a slogan is being raised very cleverly. In the name of moratorium they want to stifle the struggle of the working class. They want to ban the strike. Now they are calling it moratorium, but the ultimate aim of that is to ban the strike.

SHRI C.M. STEPHEN (Muvattupuzha) : Who told you ?

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : Morning shows the day. Something is said here but those who implement it will say, 'This is the Government order. No strike'. But may I know why you take this step ? Why don't you bring moratorium on the price line ? Why don't you bring moratorium on lock-outs ? Why don't you force the employers who have closed down their factories due to their own mismanagement to re-open them or take them over ? There is no bar to it. But may I ask, how many closed factories have been taken over by the Government ? In some cases I know, in the mills which have been taken over, there I have seen that even the minimum labour laws are not implemented.

So, on the one hand, they are giving ample scope to the big employers to loot our country and on the other hand, when there is any chance of any opposition or any protest, they want to crush it at the very moment by bringing all this sort of legislation in the form of banning strike, etc.

So, in this background we have to see the last elections and I would request the Members here to dispassionately see what has happened in West Bengal. Is it false what we are saying that the electious have been turned into a farce ? No, Sir. In the perspective of the economic situation in our country, both in agricultural and industrial sectors, the workers and the peasants and the democratic people, fighting against the onslaughts of the big monopolists and the feudal interests. are rising against the attempt of the vested interests to curb the democratic rights. In that struggle West Bengal is in the forefront and because of that, this Government, which professes that they are democracy, they are for socialism and they are for '*Garibi Hatao*', cannot tolerate anybody other than their own Party to come to power and head the Government in any State. ...(*Interruptions*)

All over India, people are experienced with our Government only for a brief period —one for a span of 13 months and another for 9 months. Is it not a fact that within that small span of time, the workers of West Bengal in jute, in textile, in engineering industries, etc. snatched away 50 crores of rupees from the pockets of the big monopoly employers ? Is it not a fact that there was a hullabaloo raised by the vested interests and the newspapers owned by them that there is no rule of law and there is no law and order ?May I ask you. Mr. Yadav was saying that there were free and fair elections. I would humbly appeal to Mr. Yadav to kindly come with us and go round West Bengal. Of the three persons you will meet, two will say that there has been some '*jua chori*', some manipulation. ... (*Interruptions*)
The whole elections were a farce. Armed gangsters were on the rampage.They adopted so many measures. Perhaps it has not come in the papers. If I am given the time, I will show you what even *Jugantar* —you know it is owned by one Congress Minister in West Bengal - - has said. He said that the election has not been fair in most of the places. The people of West Bengal cannot expect election in a peaceful atmosphere. Now, who was at the helm of affairs then ? It was under the direct regime of the President's rule. It was under the President's rule that the election was conducted. But we know that conspiracy was hatched up from here, from here, under the direct guidance of Shrimati Indira Gandhi, by which, a particular Department, - - the Research and Analytical Department, - - surveyed the West Bengal situation and gave a report saying that there is no chance of the Congress coming to power, and then conspiracy started from that day. (*Interruption*) Conspiracy started from that day and the officers were sent from Delhi, to the Writers, Building ......(*Interruption*)

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basirhat) : Write a book on Fairy Tales...

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : Is it not a fact that one newspaper in Calcutta, two or three days before the election, reported that the Inspector General of Police personally sent a covered letter to S. Ps. of districts - - a confidential letters to hand over that only to the Congress President or secretaries of the districts and not to anybody else ? I take up this challenge and ask them to disprove it. Is it not a fact ? What was the instruction ? The instruction was how to help the Congress President and the Congress candidate, how to manipulate and capture the booths. (*Interruption*)

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : On a point of order. According to the rules, if such a wild allegation is brought against any officer, or if a certain reference is made, they must have a proof for it. Without giving proof he cannot make a wild charge. He cannot say all these things.

AN HON. MEMBER : It is a newspaper report...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is making several allegations ; it is for the ruling party to contradict. Your time is up. You may try to conclude.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : They adopted 3 or 4 methods. One was, capturing booths by the use of gangsters and not to allow real, genuine voters. Even real voters could not come. Even some of the sober Congressmen complained that they could not vote. They did this method in 50 constituencies. Even then they could not have the majority. They failed. So, some other methods were adopted. They were instructed to put the ballot papers on the previous night. that is, on the 10th night, in the ballot box, and to change the ballot box after putting ballot papers stamped in favour of the Congress candidate. The ballot boxes were changed. I ask my hon. friend, Mr. Ishaque, to tell me whether it is a fact or not, that in Taitala constituency where Abul Hussain was declared elected by the returning officer, subsequently, lights were put off by the congress volunteers and the returning officer, afterwards said that not Abul Hussain but the Congress candidate was elected. The same method was adopted in Kamarhatti and Uluberia South. I will say categorically and emphatically that election has been rigged in West Bengal and democracy is at stake. *(Interruption)* Democracy is at stake in the country today. Today it is like this in West Bengal. Tomorrow it may be in Kerala. Day-after-tomorrow, it may be in U. P. Witch-hunting has been started by Shrimati Indira Gandhi. She cannot tolerate anybody opposing here and that is why this method has been resorted to. Even after the elections, vandalism and Congress as goodaism is continuing in many of the areas. Already, 30 people have been killed. Can any of my hon. friends deny this ? In how many cases have the murderers been apprehended ? Not a single one has been apprehended. The Congress volunteers are going round the areas, forcibly evicting the men belonging to the Left parties and their supporters and volunteers. Believe it or not, about 20,000 people have been forced to leave their homes and hearths. This state of affairs is still continuing.

15 hrs.

On the one side, Shrimati Indira Gandhi is taking measures to ban strikes, her partymen in West Bengal are forcibly capturing the trade union offices. If my hon. friends would come with me, I could show them that actually a union under the CITU has beeu forcibly captured by them So many trade union offices in the 24 Parganas and in Calcutta have been forcibly occupied by these goondas. When we go and complain to the police authorities, they say "What can we do ? We cannot do anything ? They are all Congressmen."

MR. DEPUTY-SPEAKER . Now, the hon. Member should conclude

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : I would coclude with an appeal both to you and to the Member of the House. Shri Chandrajit Yadav when he was speaking asked us to search our hearts I would appeal to my hon. friends opposite to search their hearts and see whether they are proceeding towards democracy or whether they have butchered democracy and raped democracy. Sir. I submit that democracy is at stake. So, I appeal.

डेमोक्रैसी बचाओं, गणतंत्र बचाओ। इसी लिये हम आप से अपील करते हैं कि इस के लिये आप आगे बढ़िये, खून खराबा बन्द कीजिये। जिन्होने खून किया है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कीजिये।

The forcible occupation of the party offfces must be stopped. I would expect that the Prime Minister would take My words seriously....

SOME HON. MEMBERS : Oh

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : All right; let a delegation be sent there, and let them judge from there own experience what is taking place in West Bengal.

With this this appeal I shall conclude and ultimately say just one thing more....

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is a no t ime for any more things now. He should concl ude.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA : Shri C. M. Stephen in the course of his speech had some reference to me, and so, I would like to offer a personal explanation. He had said that we had propagated the idea that power came out of the barrel of the gun. Sir, I submit that it is not our propaganda but it is their own propaganda which has been propagated by their people. It was the Naxalites who were propagating this, and they are now all in their camps, that is in the Congress camps.

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : डिप्टी स्पीकर महोदय, यह कोई नई बात नहीं है कि जो लोग बहुत बहादुरी बघारते हैं और फिर हार जाते हैं, उनमें यह स्पोर्ट्समैन स्प्रिट नहीं है कि वे अपनी हार बर्दाश्त कर सकें। जो चोटें उन्हें लगी है उन्हें मैं समझता हूं। जो हमारे जनसंघ के भाई हैं, सी०पी०एम० के भाई हैं और स्वतन्त्र पार्टी के भाई हैं उनको चोटें लगी हैं। दूसरों पर वे बहुत चोटें करते रहे हैं लेकिन जब उनको चोटें लगीं तो वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। डेमोक्रेसी के अन्दर बड़ी जरूरी बात है कि आदमी यह बात सीखे कि अगर वह हार जाय तो यह न कहे जैसा कि कोई खिलाड़ी अगर अच्छा नहीं होता है और वह हार जाता है तो कहता है कि एम्पायर पार्शल था, वह पक्षपात करता था, या कुछ और गड़बड़ी थी। अब आप देख सकते हैं कि जनता का जो इस दफा रुख था, जो वातावरण था देश के अन्दर वह बिल्कुल साफ था कि उन्होंने उन पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया और उनको चुनने से इंकार कर दिया और अब वह दोष कांग्रेस पार्टी पर डालना चाहती हैं कि कांग्रेस ने जो इलेक्शन्स कराए वे रिग्ड इलेक्शन्स थे, उनमें गड़बड़ी थी, अनफेयरनेस थी। वे ऐसे तमाम इलजामात लगाते हैं और इस बारे में जैसा कि मेरे साथी श्री शशि भूषण जी ने कहा कि इस बारे में जो तमाम कोरस है, तमाम शोर-शराबा है, यह जनसंघ, यह स्वतन्त्र और यह सी०पी०एम० और दूसरे विदेशी लोग जिन्होंने कि हमारे डिप्लोमेसी के मैदान में और सैनिक मैदान में हमसे हार खाई, वे तमाम एक स्वर से आवाज उठा रहे हैं। यहां के पेपर, चाइना के पेपर, अमेरिका के पेपर और दूसरे पेपर जो इन प्रतिक्रियावादी शक्तियों के समर्थक हैं वे तमाम एक ही बात कहते हैं और एक ही बात को दोहराते हैं, शायद वे समझते हैं कि बार-बार दोहराने से कोई बात सच्ची साबित हो जाए। जितनी बातें यहां पर सी०पी०एम० के मेम्बर साहब कह रहे थे अगर वह ठीक हैं तो उनके सामने फोरम खुला हुआ है। अगर उनके पास सबूत हैं तो वे इलेक्शन पैटीशन कर सकते हैं और जहां-जहां अन्याय हुआ है और ऐसी बातें हुई हैं तो वहां सबूत पेश करें और उन बातों को साबित करें कि इलेक्शन्स में गड़बड़ हुई है। उनके सामने दरवाजे खुले हैं लेकिन सिर्फ यह कह देने से और बातें बड़ी-बड़ी कर देने से मतलब हल नहीं होता है। मैं इस बात में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि सी०पी० आई० के सदस्य और दूसरे सदस्य इस बारे में उन्हें काफी जवाब दे चुके हैं लेकिन उन्हीं बातों को बार-बार दोहराया जाता है मैं समझता हूं इन पिछले वर्षों में जो बहुत बड़ी फतेह अपनी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने प्राप्त की, उससे जनता का आत्मविश्वास फिर हमने लौटाया है। हमारे विरोधी भाई हमेशा जनता के सामने हौसलाशिकनी की बातें करते थे। वह ऐसा वातावरण खड़ा कर रहे थे कि "यह सरकार क्या करेगी, इन्दिरा गांधी क्या करेगी, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया।" यहां पर हमारे वाजपेयी जी सत्याग्रह करते थे और कहते थे कि बंगला देश को हमारी पार्टी और सरकार कोई सहायता नहीं देती, और यहां पर जो इतने शरणार्थी आ गये हैं वे कैसे वापस जाएंगे? ये तमाम बातें कहकर वे जनता में अविश्वास और भरोसे की कमी पैदा करने की

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

कोशिश करते थे लेकिन इस समय जो कुछ भी हमारी नेता श्रीमती गांधी ने किया वह यह कि उन्होंने जनता के अन्दर एक वातावरण पैदा किया, जनता के अन्दर आत्मविश्वास पैदा किया जिससे आज एक ऐसा वातावरण है और लोगों को भरोसा है सरकार पर। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और उस युद्ध में हम कामयाब हुए, इसमें यह ठीक है कि सेना की रणबातुरी थी, लेकिन यह सब चीजें एक दिन में तैयार नहीं हुईं। पिछले 6 सालों से, 1966 से जब कि प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में इस देश की बागडोर ली, तब से वे तैयारी कर रही थी जिससे देश को अपने पैरों पर खड़ा किया जाय। देश की सेना को और हथियारों के सम्बन्ध मे और युद्ध की जो शस्त्र सामग्री है उसके लिहाज से, गोया कि हर लिहाज से, देश को मजबूत किया जाय। क्यो हमारी सेना और हमारी नेवी लड़ सकी और क्यों इतने शानदार कारनामे दिखा सके? क्यों हमारी सेना अपने हथियारो की सहायता से पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर सकी और हम अपनी ताकत दिखा सके और सफलता पा सके और क्यो ये फोर्सेज आपस में मिलकर काम कर सकी, क्यों हमारी अर्थनीति और हमारा आर्थिक ढांचा इतनी बड़ी विपत्ति का मुकाबला कर सका कि एक करोड़ लोग यहां आ गये और हम उनको संभाल सके और साथ ही साथ युद्ध का खर्च भी करते रहे और देश की स्थिति प्रायः ठीक रही। यह ठीक है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो कुछ न कुछ घबड़ाहट पैदा होती है, कुछ न कुछ प्राइसेज में उथल-पुथल होती है लेकिन मुल्क पर जो इतनी लम्बी विपत्ति आई, जो इतनी बड़ी उथल-पुथल हुई, हमारे आर्थिक ढांचे ने उसका बड़ी मजबूती से मुकाबला किया। इस सब की वजह क्या है? इसके पीछे पिछले पांच छः साल से लगातार गवर्नमेंट की और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की तैयार थी और उनकी नीति थी जिससे हम इस बात को कर सकें। उनकी नीति की सफलता यह है कि आज दुनिया में हमारे देश की इज्जत बहुत बढ़ी है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। यहां एशिया के अन्दर एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तमाम एशिया की जो नीति है, विदेशों से जो हमारी डिप्लोमेसी है, उन तमाम बड़ी-बड़ी शक्तियों में एक नया संतुलन उत्पन्न हुआ है। एशिया के शक्ति संतुलन में आज हमारी भी ऊंची हैसियत है, हमारा सम्मान है, आज हम रास्ता दिखाने वाले बन गये हैं एशिया मे उन ताकतो के खिलाफ जो ताकतें चाहती है कि साम्राज्यवाद रहे, जो ताकतें चाहती है कि लूटखसोट होती रहे। हमने वीयतनाम मे उसके दूतावास को पूरा दर्जा दिया। उनके साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हुए और दूसरे देशो के साथ भी हमारे सम्बन्ध अच्छे हुए। अरब देशो के साथ भी, बावजूद इसके कि उन्होने बंगला देश को आज तक स्वीकार नही किया है, हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं, यह हमारी नीति की सफलता है और इस के साथ ही हमारी जो प्रतिष्ठा बनी है अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे, वह इस बात का प्रमाण है कि हमारी नीति ठीक थी और जो लोग हौसलाशिकनी करते थे और कहते थे कि यह नीति गलत है आज उन्होने फल भोग लिया क्योंकि लोगों ने देख लिया कि जब इन पर जिम्मेदारी डाली गई तो ये पार्टियां आपस मे लड़ती रही। ये पार्टियां पहले कांग्रेस को ताने देती थी कि हम लोग आपस मे झगड़ते हैं। कहीं पर भी यह पार्टियां चाहे सी०पी०एम० हो, जनसंघ हो, अकाली दल हो, संसोपा हो या इनका गठबन्धन कहीं पर हुआ हो, ये अपने आपको सम्भाल नहीं सकी हैं। कहीं पर भी उनकी हुकूमतें ज्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकीं। चार छः महीने मे उनकी हुकूमतें टूटती नजर आईं। ऐसी पार्टियां जो फिरकापरस्त पार्टियां हैं, जनता को और देश को क्या दे सकती हैं। इनको जनता ने अच्छा उत्तर दिया है, जनता ने करारा जवाब दिया है। ये बौखला गए हैं और इसी वजह से इस तरह की

बातें कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गलत इलेक्शन हुआ है। इनको पता नहीं दुनिया के इस बारे में क्या विचार हैं। दुनिया देख रही है कि जनता की क्या भावनायें हैं। जो कुछ भी हमने सफलतायें प्राप्त की हैं, वे हमारी नीतियों की वजह से ही हमें प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको जनता ने स्वीकार किया है, उनको प्रतिष्ठित किया है। साम्प्रदायिक दलों, प्रतिक्रियावादी दलों की इन इलेक्शन्ज में पराजय हुई है। इन पार्टियों के लोग जो हारे हैं, उनके प्रति मुझे वैयक्तिक तौर पर सहानुभूति है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि यह सिद्धांतों की पराजय हुई है और उनको अपने सिद्धान्तों को, अपनी नीतियों को बदलना चाहिए और समझना चाहिए कि जनता किस प्रकार की नीति चाहती है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भूत की चर्चा की है और भविष्य के लिए जो बातें कही हैं वे भी बहुत सुन्दर बातें हैं। रोम एक दिन में बड़ा नहीं हो गया था। एक दिन में देश की तमाम समस्यायें हल नहीं हो सकती हैं। लेकिन जिस दिशा की ओर उन्होंने संकेत किया है, वह बिल्कुल ठीक दिशा है। हम देख रहे है कि भूमि सुधार का प्रश्न हमारे सामने है। आर्थिक नीति की भी पुनर्रचना का सवाल हमारे सामने है। और भी बहुत से सवाल हमारे सामने हैं। इनके बारे में हमारी नीति क्या होगी, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने एड्रेस में किया है। इस सबके पीछे जो भावना है, इसकी जो टोन है उसे भविष्य के प्रति आशा की भावना ही बंधती है, और मैं समझता हूं कि हमें इसमें कामयाबी अवश्य मिलेगी।

अन्त में अपनी कांस्टीट्यूएंसी चंडीगढ़ के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। चंडीगढ़ की दशा तीनों लोकों से न्यारी है। लोकतंत्र के प्रवाह से इस सुन्दर नगर को अलग रखकर वहां नौकरशाही को एकाधिपत्य दे दिया गया है। जो जनता पर हकूमत करना चाहते हैं, जनता की सेवा नहीं। चंडीगढ़ ही सारे देश में ऐसा नगर है जहां एक दो बातों की तरफ मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बेकारी समस्या एक बहुत विकट समस्या है। यह समस्या मुंह बाए हमारे सामने खड़ी है। मुझे दुख है कि हमारी नौकरशाही इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जो रुपया रखा गया उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सके। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में टास्क फोर्स की बात कही है जो एग्जेमिन करेगी कि हमारा रुपया खर्च क्यों नहीं होता है, रुपया रखा जाता है तो क्या वजह है कि वह बच जाता है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि हमारी जो नौकरशाही है, हमारा जो शासन-तंत्र है, उसको बहुत सम्भालने की जरूरत है। जो फिजूल खर्च होता है, उसको रोकने की जरूरत है। फालतू कर्मचारी हमने रखे हुए हैं, उसको देखने की जरूरत है। अगर अच्छी तरह से एग्जेमिन किया जाए तो आधे कर्मचारियों से काम चल सकता है। हमारे शासन का जो ढांचा है उसमें हमने फालतू आदमी बहुत रखे हुए हैं। काम थोड़ा होता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। इन चीजों को हमें देखना चाहिये।

मैं चंडीगढ़ से चुनकर आया हूं और उसके सम्बन्ध में मैं एक दो बातें भी कहना चाहता हूं। आपको मालूम ही है कि पीछे चंडीगढ़ के भविष्य के बारे में काफी चर्चा होती रही है, काफी विवाद इसके सम्बन्ध में रहा है। इस विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री के एवार्ड के मुताबिक अगर इसको पंजाबी सूबे में मिलाना हो तो उसमें मिला देना चाहिए और इसको अगर सेंटर के नीचे रखना है तो कम से कम वहां का जो कर्मचारी-तंत्र है, उस को ठीक किया जाए। कोई न कोई जनता के साथ उसका सम्पर्क होना चाहिए। आज के

[श्री अमरनाथ विद्यालंकार]

कर्मचारी-तंत्र में जनता की कोई परवाह नहीं की जाती है। जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा सम्पर्क पैदा करने की कोशिश होनी चाहिये। इसी तरह से चंडीगढ़ में जो सेंटर के एम्प्लायीज हैं उनको मंहगाई भत्ता पंजाब और हरियाणा के लोगों के हिसाब से मिलता है। वहां लोगों की शिकायत है कि चंडीगढ़ का जो स्पेशल एलाउंस है, चंडीगढ़ एलाउंस जो है, वह उनको मिलना चाहिये। इसी तरह से चंडीगढ़ के अन्दर, आप सुनकर हैरान होंगे, कि सारे देश में किरायों पर रेस्ट्रिकशन है, लेकिन वहां कोई रेस्ट्रिकशन नहीं है। मकानों के मालकों पर कोई मर्यादा नहीं। वे लोग जितना चाहें और जब चाहें किराया बढ़ा सकते हैं। जब चाहें मकान खाली करा सकते हैं। वहां के रेंट्स पर रेस्ट्रिकशन होनी चाहिये। अधिकारियों का सलूक लोगों के साथ बेहतर होना चाहिये। आज वह नहीं है। अफसरशाही ने चंडीगढ़ को आज अपनी एक एस्टेट समझ लिया है और एरोगेंट तरीके से वह शासन करती है। इन हालात को बदलना चाहिये और समझना चाहिये कि जहां चंडीगढ़ एक सुन्दर शहर है, वहां पर वह सिर्फ चन्द अफसरों या बड़े बड़े रिटायर्ड अफसरों के ही रहने की जगह नहीं है, केवल अमीर लोगों के रहने की ही जगह नहीं है, बल्कि गरीबों के भी रहने की वह जगह है। जो अफसर जनता के साथ सहयोग नहीं करते, सम्पर्क नहीं रखते, उसकी राय से नहीं चलना चाहते हैं, उनको आप रोकें और उन में आप सुधार लायें। जनता अफसरशाही से बहुत परेशान है। अफसरों का रुख जनता के प्रति कठोर और अक्खड़पन का है, दोस्ती और सहानुभूति का नहीं। इसे आप सुधारिये।

*SHRI T. S. LAKSHMANAN (Sriperumbudur) : Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, our President, Shri V. V. Giri, is a renowned labour leader and before he became the President he had devoted his entire life to the cause of welfare of labour. The workers and the labourers had implicit faith in his leadership.

He was for some time the Labour Minister in the Cabinet of Shri Jawaharlal Nehru, who was acclaimed as the light of Asia, the uncrowned King of India, the lustrous gem of humanity. The entire country knows that Shri V.V. Giri resigned his ministership from the Cabinrt of such a leader simply because he disagreed with certain policies of labour welfare being followed by the Government. I would say that this is an unforgettable event in the history of our country.

To my dismay and to the disappointment of labour, there is no reference at all in the President's Address about the problems of labour and the Government's policies of labour welfare. The workers and labour were eagerly expecting that the President's Address would reflect their hopes and aspirations. But I am sorry to point out that the President's Address draws a blank in this respect.

It is an acknowledged fact that the agriculturists are the backbone of our country and agriculture is the life source of our economy. The agriculturists go to work when the cock crows, shed their blood and sweat in different kinds of activities throughout the day and return home when the owl hoots. There is no reference at all to the problems of agriculturists and agricultural labour in the President's Address.

We are in the 25th year of our Independence and our population has crossed the figure of 55 crores. The vast majority of our people are agriculturists, weavers, and factory workers. The country knows that unless these people work hard, other will not get their food and clothing. What is the position of these people ? Are they in a position to buy their daily necessities for a month ? They go to shops every day and purchase their daily needs. The prices of daily needs are going up hour by hour and in fact, minute by minute. There is no mention at all the in the President's Address about the steps being taken by the Government for arresting the phenomenal rise in prices. In 1970 the price rise was 6.2% in 1971 the increase went up to 9.5%. In

January 1972, the price increase was 4% higher than what it was in January 1971. In 1955 the price of foodstuffs was 92 Points and in 1971 it was 235 points. What will the poor workers do if the price rises like this ? Have their wages gone up proportion to the rise in price ? The answer is in the nagative. The hopes of harassed workers have been belied by the President's Address because the Address has nothing to say about the steps being taken by the Government to control the price rise.

It is also regrettable that the President Address does not say anything about the imminent necessity of providing basic and minium wages to the workers. It the workers are not given minimum wages, I wonder how the Government will be able to achieve the objective of establishing democratic socialism in our country. Only when the workers are given the minimum wages, the productivity will pick up which in turn will bring us nearer to tho goal of self-reliance.

Sir, we find that there are inter-State water disputes in our country. For example there is the long standing Cauvery Water dispute between Tamil Nadu and Mysore. How these disputes are going to be resolved? There is no inkling about this in the President's Address. The people of Tamil Nndu are greatly agitated because the dispute may be setted against their interests because of Congress Party coming back to power in Mysore. If the rivers flowing across the States are declared as national rivers, there will be no room for such inter-State water disputes.

In the Fourth Five Year Plan, the proposed outlay on Rural Water supply is Rs. 125 crores. But, just before the elections to the State Assemblies, keeping an eye on the votes of rural people, the Central Health Minister, Shri Uma Shankar Dikshit, announced on Ist March 1972 in New Delhi that the Government have formulated a Five Year Rural Water Supply Scheme at a cost of Rs. 110 crores and it has been sent to the Planning Commission for further processing. When will this scheme be implemented ? In which Five Year Plan this scheme will be incorporated ?

I am at a loss to know that in theFourth Plan there is no provision for rural housing. The Bhagavati Committee in its interim report has stated that a sum of Rs. 125 crores will be provided during 1972-1974 for rural housing. But, what do we find in this years budget of the Government of India ? A sum of Rs. 125 crores has been allocated for rural housing, slam clearance, primary education, unemployment in rural areas and so many other things. What is going to be the share of rural housing in this amount of Rs. 125 crores ? One is forced to come to the conclusion that practice is different precept. The President says something and the Government does some other things.

The National Council of Science and Technology has been endeavouring to find out new import substitutes with a view to reducing the drain of our valuable foreign exchange. What do we see today ? The Government of India have offered many concessions, inducements and incentives for attracting British capital and technology. Is this not going to affect the country's efforts to develop iddigenous knowhow ? Will not our productivity be jeopardised ? I want to have a clarification for this contradiction.

The President in his Address has said that the State Governments should show some restraints in getting overdrafts from the Reserve Bank of India. The Government of India are also thinking of prohibiting the States taking overdrafts from the Reserve Bank. It is axiomatic that for achieving economic independence the State Governments have to increase the productivity, have to encourage the setting up of new industries, have to give a helping hand to the struggling industries. As the States have very little potential for raising additional revenues they go to the Reserve Bank for overdrafts so that they can concentrate on these constructive activities. Is this a crime ? Only when there is industrial growth, there will be economic development. After appropriating all the revenue raising resources, if the Centre thinks of putting curbs on tendency of States to take overdrafts, will there be appreciable increase in our productivity ? The quantum of overdrafts taken by the States is not even one-fourth of the loss suffered by the public sector undertakings of the Central Government.

[Shri T.S. Lakshmanan]

The President in his Address has enumerated the proposed legislations of the Government of India. Last year the Drug Prices (Control) Act was enacted by this House, and in that the ceiling of profit for the drugs manufacturing companies was fixed at 15%. What do we see? The drugs manufacturing companies are making huge profits inspite of this Act. For example, the Warner Hindustan's profit was 20%. The profit of Pfizer Company was 26.4%. I would like to know what action has been taken against these companies under the penal provisions of the Drug Prices (Control) Act.

The President says that our economy was not stagnant last year. But the real picture is, in 1971-1972 while the exports have gone up by 3.5%, which is comparatively very much less than previous years' achievement, the imports have gone up by 18.5%.

With this imbalance in the country's import and export trade, do you think that the economy would have made progress? Let us take another example. The production of virginia tobacco in 1971-72 was 1500 lakh kilos. The internal consumption and the export came to 950 lakh kilos. Britain has reduced its import of tobacco by by 25%. On account of excessive excise duty on tobacco, the internal consumption has also come down, resulting in the glut of tobacco. What steps have been taken by the Government to remedy this situation?

The president has proclaimed that the Government's responsibility towards the families of those who sacrificed their life in the recent Indo-Pak war would be discharged in full. In big cities and towns, you cannot acquire or construct a house in two months. According to the rules of the Governments, the families of officers killed in action can stay in the Government accommodation for only two months. Where will they go after two months? The expenditure of concessions and amenities offered to these families comes to Rs. 3 crores per annum, which is in fact less than a day's expenditure during Indo-Pak war. Is this really the gratitude we show to the kith and kin of the valiant sons of India who sacrificed their life in defence of the country?

I am sorry to say that the President's Address is just an expression of sanctimonious sentiments in flowery language. It does not reflect the Central Government's capability to achieve the set goals.

As I pointed out earlier, the agriculturists and the workers, who form the majority of our population and on whose efforts the rest of the population survive, are faced with innumerable problems. If their problems are not solved expeditiously, all our efforts on economic development will be set at naught.

With these words, I conclude.

श्री हरी किशोर सिंह (पुपरी) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से भ्राम चुनावों के सम्बन्ध में भ्रपने सी० पी० (एम०) के मित्रों के भाषण सुने। इस पर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर इतने बड़े देश मे, इस महान् जनतन्त्र मे, काफी बडा चुनाव होता है। उस मे थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर हो सकती है। मैं नही कहता कि उस मे गड़बड़ी नही हुई होगी। थोड़ी बहुत हुई होगी। लेकिन सारे चुनाव पर यह आरोप लगाया गया है कि यह चुनाव गलत हुआ है, जनतंत्र की हत्या हो गई है, इस देश से जनतंत्र समाप्त होने जा रहा है, इस देश में तानाशाही मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है और देश की प्रधान मंत्री तानाशाह बन रही हैं। मुझे इस पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। मार्किसस्ट पार्टी ने इस चुनाव के बारे मे बहुत बडा मन्सूबा बांधा था। चुनाव के दो दिन पहले उस ने यह घोषणा भी की थी कि बंगाल में हमारी विजय निश्चित है। सम्भव है कि इतनी बड़ी पराजय से इन लोगों को बहुत धक्का लगा हो और उसके कारण वे भ्रपना संतुलन खो बैठे हो और आवेश में ऐसे गंभीर भ्रारोप लगाते हों जो बिलकुल निराधार हैं।

मैं तो उम्मीद करता था कि जिस तरह 1967 के चुनाव में कई प्रान्तों में पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज अपने कार्यकर्ताओं,

नीतियों और नेतृत्व में परिवर्तन किया, उसी तरह मार्क्सिस्ट पार्टी भी इस चुनाव के परिणामों से सबक ले कर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर पुनर्विचार करेगी और देखेगी कि उस की नीतियों और कार्यक्रमों में क्या त्रुटियां हैं और उस के नेतृत्व ने कहां गलती की है।

1967 के आम चुनाव के बाद बंगाल मे किस तरह का वातावरण पैदा किया गया था ? क्या घेराव जनतांत्रिक परम्परा के अनुकूल था ? क्या घेराव संसदीय जनतत्र को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था ? बंगाल में घेराव और हिंसा का जो वातावरण पैदा किया गया था, क्या वह जनतंत्र के अनुकूल था ? मैं चाहता हूं कि मार्क्सिस्ट पार्टी के लोग इस पर गम्भीरता से विचार करें, क्योंकि 1967 के आम चुनाव के बाद बगाल मे घेराव और हिंसा का जो वातावरण पैदा किया गया, उस का परिणम यह हुआ कि बंगाल मे हड़ताल, घेराव, औद्योगिक प्रतिष्ठानो का बन्द होना और बेकारों की संख्या मे बढ़ौतरी एक आम बात हो गई। कोई आदमी बंगाल मे आना नही चाहता था। बिहार के बहुत से लोग बंगाल में रहते हैं। आये-दिन हम साधारण लोगों और मजदूरों से बगाल की कहानी सुनते थे. तो हम को बहुत तकलीफ होती थी।

MR. DEPUTY-SPEAKE : He May continue his speech on Monday because we have to take up non-official business now.

15.30 hrs.

PRACTISING ARCHITECTS BILL*

SHRI K. LAKKAPPA (TUMKUR) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the registration of practising architects and for matters connected therewith.

MR DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the registration of practising architects and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI K. LAKKAPPA : I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(*Amendment of articles 74, 75 etc.*)

SHRI A.K. GOPALAN (Palghat) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI A.K. GOPALAN : I introduce Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of Eighth Schedule*)

DR. KARNI SINGH (BIKANER) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. KARNI SINGH : I introduce the Bill.

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 30.3.72.